माननीय सदस्य या किसी भी माननीय नेता का नाम लू इस सिलसिले मे। यह अच्छा नही होगा। (व्यवधान) . मेरे पास सूचना है कि किस किस राष्ट्रीय नेता के पास, किस किस समस्तसदस्य के पास या किन मत्रियो के पास इस प्रकार के टेलीफोन काल और चिट्ठिया आई है लेकिन मैंने इरादतन नाम नही लिया। मैं नाम लेना नही चाहता और नाम लेना ठीक भी नही होगा।

सरकारी कार्यालयो में हिन्दी का प्रयोग

***409. श्री चिरजीव झा : क्या** गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी अधीनस्थ कार्यालयो को यथासम्भव अधिकाधिक हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने का आदेश दिया गया है

(ख) यदि हा, तो केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने अधिनस्थ कार्यालय है जहा अभी केवल अग्रेजी का प्रयोग होता है, और

(ग) हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहन देने के आदेशो का कहां तक पालन हो रहा है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) हिन्दी भाषी क्षेत्रो मे स्थित अधीनस्थ कार्यालयो मे हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये सभी मत्रालयो / विभागो को समय समय पर अनुदेश दिये जाते रहे हैं। इन आनुशो के पालन पर विभिन्न मत्रालयो विभागो/कार्यालयो मे स्थापित राजभाषा कार्यान्वयन समितियो द्वारा निगरानी रखी जाती है। इन समितियो को अनुदेशो के कार्यान्वयन का तिमाही पुनरीक्षण करना होता है। विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयो मे हिन्दी के प्रयोग मे की गई प्रगति के बारे मे अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध नही है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों की सख्या बहुत अधिक है और वे सारे देश म फैले हुए है। आकडे एकत्र करने मे लग वाला समय, श्रम तथा व्यय प्राप्त कियेने जाने वाले सम्भावित परिणामो के अनुकूल नही होगे।

श्री चिरजीव झा मत्री ने जिन अनुदेशो का अपने उत्तर मे जिक्र किया है उस सबन्ध मे मैं जानना चाहता हू कि जब उन अनुदेशो के पालन पर विभिन्न मत्रालयो, विभागो एव कार्यालयो मे स्थापित राज भाषा कार्यान्वयन समितियो द्वारा निगरानी रखी जाती है और जब इन समितियो को कार्यान्वयन का हर तिमाही मे पुनरीक्षण होता है तब फिर क्या बात है कि हिन्दी के प्रयोग मे की गई प्रगति की अपेक्षित सूचना सहज मे उपलब्ध नही है ? क्या हर तिमाही मे पुनरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इसकी स्पष्ट सूचना इस सदन को नही दी जा सकती है ?

फिर अतिरिक्त श्रम, समय और व्यय की आवश्यकता कहा पडती है ? क्या इसका हम यह अभिप्राय लगाए कि मत्री जी के अनुसार हिन्दी के प्रयोग म अपेक्षित प्रगति नही हुई है ?

श्री राम निवास मिर्धा मैंने यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ कार्यालय सैंकडो है और सब जगह वे फैले हुए है। यह बताना कि किस मे हिन्दी का प्रयोग कितना होता है इस सूचना को इकट्ठा करने मे समय लगेगा मेरा अभिप्राय केवल यही था। जहा तक तिमाही रिपोर्टों का सवाल है वे हमेशा तैयार की जाती है। सालाना रिपोर्ट भी सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिस मे उल्लेख होता है कि कितना कार्य इस क्षेत्र मे हुआ है और उन रिपोर्टों को अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो उनको आभास होगा कि

प्रगति हुई है और निश्चित ही प्रगति हो रही है ।

श्री चिरंजीव झा : क्या यह बात सच है कि अभी तक केन्द्रीय सरकार सिर्फ नौ राज्यों के साथ हिन्दी में पत्राचार करती है?. मैं जानना चाहता हूं कि अन्य राज्यो के साथ कब तक हिन्दी में पत्राचार करने की योजना है और अभी अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी मे भी सभी राज्यो के साथ पत्राचार क्यो नही प्रारम्भ किया जाता ?

क्या जीवन बीमा निगम जिस का सम्बन्ध गांव के हर व्यक्ति से है सभी प्रपत्र अंग्रेजी मे ही छापता है और यदि हा तो यह कहा तक उचित है ? क्या इसकी व्यवस्था नही की जा सकती है कि अंग्रेजी के साथ साथ ये प्रपत्र हिन्दी में भी छापे जाए ?

श्री राम निवास मिर्धा सरकार की जो हिन्दी के सम्बन्ध मे नीति है उसको हम लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन या दूसरे जो कारपोरेशन है उन पर भी लागू करने का निर्णय बहुत समय पूर्व ले चुके है । उन से समय समय पर यह कहा जाता है कि वे भी विशेष तौर से जो उनके कार्यालय हिन्दी भाषी क्षेत्रो मे स्थित है वहा हिन्दी का प्रयोग करे .....

कुछ माननीय सदस्य : कही नही हो रहा है ।

श्री राम निवास मिर्धा : इस विषय मे मे जो भी प्रगति होती है उसको एक सालाना एसेसमेंट रिपोर्ट हम सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और जैसा मैने निवेदन किया है उस मे अवश्य कुछ न कुछ गति हर क्षेत्र में हुई है और जितनी अपेक्षा की जाती और माननीय सदस्य और सरकार जितनी चाहते है सम्भवत: उतनी न होसकी हो, पर प्रयास निरंतर जारी हैं ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Discussion of law and order problem at the recent Conference of Chief Ministers of States

*401. SHRI R. S. PANDEY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the deterioration in law and order situation in the country was discussed at the recent Conference of Chief Ministers of States,

(b) whether any concrete measures have been worked out to improve the situation, and

(c) if so, the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMA SHANKER DIKSHIT) (a) to (c) A conference of Chief Ministers of States was held in the capital on 24th February, 1973, at the instance of the Ministry of Food and Agriculture to discuss and finalise the steps necessary to implement the Government's decisions regarding procurement and take over of wholesale trade in foodgrains No item relating to the law and order situation in the country was sponsored by the Ministry of Home Affairs for discussion at this conference.

Co-ordinated research plan made by the National Committee on Science and Technology

*405 SHRI DEVINDER SINGH GARCHA·

SHRI RAMSHEKHAR PRASAD SINGH:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state·

(a) whether the National Committee on Science and Technology has proposed a Rs. 10 crore co-ordinated research plan which has identified a